निर्यात पर अधिकाधिक जोर देने के विचार से वित्तीय संस्थान ऐसी निर्यातोन्मुखी इकाइयों को तरजीह दे रहे हैं जो इस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों ने प्रवर्तित की है और जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के धागे उत्पादन का सुनिश्चय करने के लिए अत्याधुनिक उपस्कर लगाने के इच्छुक हैं। विद्यमान सहकारी मिलों का कार्य समान्यता असन्तोषजनक रहा है और उन पर वित्तीय संस्थानों के बड़ी मात्रा में अतिदेय बकाया है। आईडीबी आई ने महाराष्ट्र सरकार को विद्यमान सहकारी कताई मिलों के अतिदेयों को समाप्त करने तथा उनके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की सलाह दी है।

Waiving of loan by Vijaya Bank

930. SHRI K. R. MALKANI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has to be drawn to the news-item published in the Economic Times of 31st May, 1994 alongwith other national dailies under the caption 'LF charges Murthy with misuse of office'; and

(b) if so, what are the details thereof and what action Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) In terms of the provision contained in Section 13(1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Acts, 1970 and 1980, the nationalised bank shall not divulge any information relating to or to the affairs of its constituents except in circumstances in which it is in accordance with law or practices and usages customary among bankers. In the light of these statutory provisions information relating to a constituent of Vijaya Bank cannot be divulged.

Government have, however, examined the matter in consultation with Vijaya Bank and RBI in the light of the news-item which appeared in newspapers. In the recent past Vijaya Bank have approved a number of compromise proposals. A majority of these proposals pertain to credit facilities sanctioned during 1985 to 1997. The write offs in many cases have been necessitated either because of improper/invalid documentation, or erosion in the worth of securities etc. Experience of the bank in respect of suit filed accounts have also conditioned its decisions in such cases. The Board of Directors of Vijaya Bank have also approved certain guidelines for arriving at compromise proposals and such proposals are decided as per the approved guidelines.

भारतीय बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि

931. **श्री गोविन्दराव आदिक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बैंकों को पूरी वसूली न होने की स्थिति का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उन्हें कभी-कभी पूरी वसूली प्राप्त नहीं होती है जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी उसे छोड़ देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय बैंकों द्वारा कितनी वसूली की गई ;

(ग) क्या सरकार वसूली के संबंध में कोई नयी नीति बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, मार्च, 1993 के अंत की स्थिति के अनुसार, सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंधित बकाया अग्रिमों और अतिदेयों की कुल राशि क्रमश: 125955 करोड़ रु० और 22989 करोड़ रु० थी । चूंकि बैंक ऋणदाता संस्थाएं हैं, इसलिए उधार दी गई निधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सभी प्रणालियों और क्रियाओं के बावजूद कतिपय ऋण राशियां अशोध्य हो जाती हैं । अतिदेयों और अशोध्य ऋणों की बारदातों को कम करने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे अलग अलग राशियों की स्थिति दर्शाने के लिए एक व्यापक और समान ग्रेडिंग प्रणाली शुरु करने के लिए कहा है, ताकि इन आग्रमों की कारगर निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकें । उनसे यह भी कहा गया है कि वे सर्वाधिक अशोध्य खातों की वसूली पर नजर रखें । सामायत:, बैंक वसूली के सभी अवसर समाप्त हो जाने के बाद और अपने हितों की सुरक्षा करने तथा परिसीमन कानून की अवधि के अन्दर प्रतिभूति को प्रवर्तित करने के लिए मुकदमें दायर करते हैं ताकि उधारकर्ताओं द्वारा अदा न की गई शेष बकाया राशियों की वसूली की जा सके । बैंक अतिपय अग्रिमों को अशोध्य ऋणों के रूप में केवल तभी बट्टे खाते डालते हैं जब वे इस बात से पूर्णतया संतुष्ट होते हैं कि ये अग्रिम अंततोगत्वा वसूली योग्य नहीं है इस प्रकार, बैंक के हितों की सुरक्षा करने के लिए चूक वाले खातों की सतत निगरानी और समीक्षा की जाती है । हाल ही में, बैंकों को देय ऋणों के शीघ्र न्यायानर्णयन और वसूली के लिए तथा उससे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 अधिनियमित किया गया है ।

Pension to LIC employees

932. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the amount of pension which is given to Life Insurance Corporation Pensioner;

(b) whether dearness allowance and the benefit of family allowance is also being given and if so, since when and to whom; and

(c) whether peons are also entitled to the benefits?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) At present no pension scheme is available to the employees of the Life Insuarnce Corportation of India (LIC). However on the basis of a Memorandm of Understanding reached between the Employees Associations and the Management of LIC, a draft pension scheme which covers all employees including peons has been formulated and sent to the Government by the LIC. This is under consideration of the Government.

"आयकर अपील प्राधिकरण" के समक्ष लम्बित मामले

933. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री कनक सिंह मोहनसिंह मंगरोला :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "आयकर अपील प्राधिकरण" के समक्ष लम्बित मामलों की संख्या एक लाख से अधिक हो गई है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्राधिकरण को कितने मामले प्राप्त हुए और उसके द्वारा कितने मामले निपटाये गये ; और